कार्यालय मुख्य निर्वाचन अधिकारी, दिल्ली

ओल्ड सेंट स्टीफंस कॉलेज बिल्डिंग, कश्मीरी गेट,

नई दिल्ली – 110006

सीविजिल पर 7500 शिकायतें प्राप्त हुईं, 99% निवारण दर; 2780 एफआईआर दर्ज; 220 करोड़ रुपये मूल्य की जब्ती दर्ज की गई

दिल्ली में स्वतंत्र, निष्पक्ष और सुचारू विधानसभा चुनाव के लिए 1.8 लाख से अधिक चुनाव कर्मी अथक परिश्रम कर रहे हैं

चुनावकर्मी बदनाम करने वाले अभियानों और शिकायतों के विरुद्ध कार्रवाई न करने के झूठे आरोपों से अविचलित हैं

प्रत्येक शिकायत का जवाब दिया जा रहा है और गहन मूल्यांकन के बाद स्थापित प्रक्रिया के अनुसार कार्रवाई की जा रही है: सीईओ दिल्ली

नई दिल्ली **दिनांक: 3 फ़रवरी 2025**

दिल्ली के मुख्य निर्वाचन अधिकारी (सीईओ) का कार्यालय, दिल्ली विधानसभा 2025 के लिए स्वतंत्र, निष्पक्ष और पारदर्शी चुनाव कराने के लिए अपनी प्रतिबद्धता की पुष्टि करता है। आदर्श आचार संहिता लागू होने के बाद से, सीविजिल के माध्यम से 7,499 शिकायतें प्राप्त हुई हैं। इनमें से 7,467 शिकायतों का सफलतापूर्वक समाधान किया गया है। केवल 32 मामले प्रक्रियाधीन हैं, जो अधिकारियों द्वारा की गई त्वरित कार्रवाई को दर्शाता है। उल्लेखनीय रूप से, 90% से अधिक शिकायतों का 100 मिनट के भीतर समाधान किया गया, जो निवारण तंत्र की प्रभावशीलता को रेखांकित करता है।

सुविधा प्लेटफॉर्म: चुनाव अनुमतियों को सुव्यवस्थित करना- चुनाव संबंधी गतिविधियों को सुचारू रूप से चलाने के लिए, सुविधा प्लेटफॉर्म ने राजनीतिक दलों और उम्मीदवारों से अनुमति अनुरोधों को संसाधित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है।

चुनावों की घोषणा के बाद से:

कुल 43,992 अनुमति अनुरोध प्राप्त हुए हैं। इनमें से 34,823 अनुरोधों को मंजूरी दी गई है। स्थापित दिशानिर्देशों का पालन करते हुए लगभग 8,900 अनुरोधों को खारिज कर दिया गया है। 113 आवेदन दोहराव या अमान्य होने के कारण रद्द कर दिए गए हैं।

भारत चुनाव आयोग ने 1.8 लाख से अधिक कर्मियों को तैनात किया है जिनमें 11 डीईओ; 15 डीसीपी; 77 केंद्रीय पर्यवेक्षक; 70 आरओ; 232 एआरओ, 2009 सेक्टर अधिकारी, 940 एफएसटी, 933 एसएसटी,

324 वीवीटी, 316 वीएसटी; अर्धसैनिक बलों की 220 कंपनियां जिनमें 16,000 से अधिक कर्मी शामिल हैं; 35,600 दिल्ली पुलिस कर्मी; 19,000 होमगार्ड; दिल्ली विधानसभा चुनाव 2025 के लिए 1314 बीएलओ पर्यवेक्षक और लगभग 69,000 मतदान कर्मी तैनात किए गए हैं। निष्क्रियता के निराधार आरोपों के बावजूद वे चौबीसों घंटे अथक परिश्रम कर रहे हैं। निष्क्रियता के आरोप लगाना चुनावी माहौल को खराब करने और चुनावी प्रक्रिया के इर्द-गिर्द नकारात्मक आख्यान बनाने का प्रयास है।

इन चुनावों में प्रलोभनों पर सख्त कार्रवाई के तहत 220 करोड़ रुपये से अधिक की नकदी, शराब, ड्रग्स, मुफ्त उपहार, कीमती धातु आदि की जब्ती दर्ज की गई है। इनमें सबसे बड़ा घटक 88 करोड़ रुपये की ड्रग्स है, इसके बाद 81 करोड़ रुपये से अधिक की कीमती धातुएं और 39.87 करोड़ रुपये की नकदी है। यह 2020 के दिल्ली विधानसभा चुनावों की तुलना में लगभग चार गुना वृद्धि दर्शाता है, जहां कुल जब्ती 57.5 करोड़ रुपये थी। विभिन्न आबकारी अधिनियम, शस्त्र अधिनियम और संपत्ति विरूपण अधिनियम के तहत 2780 एफआईआर पहले ही दर्ज की जा चुकी हैं, जो 2020 के चुनावों के दौरान दर्ज की गई 2067 एफआईआर से अधिक है, और अधिकारी उल्लंघनकर्ताओं के खिलाफ त्वरित कानूनी कार्रवाई सुनिश्चित कर रहे हैं।

प्लेटफॉर्म निर्बाध रूप से काम करने में मदद करता है, आदर्श आचार संहिता (एमसीसी) का कड़ाई से पालन करते हुए अनुमति देने में पारदर्शिता और दक्षता सुनिश्चित करता है।

चुनाव अधिकारियों के खिलाफ निरंतर और अनुचित आलोचना के बावजूद, सीईओ, जिला चुनाव अधिकारी (डीईओ), पुलिस उपायुक्त (डीसीपी) और रिटर्निंग अधिकारी (आरओ) समय पर और निष्पक्ष तरीके से चिंताओं को दूर करने में दृढ़ रहे हैं। चुनाव प्रक्रिया शुरू होने के बाद से, सोशल मीडिया के माध्यम से 115 से अधिक शिकायतों का सक्रिय रूप से जवाब दिया गया है, जिससे यह सुनिश्चित होता है कि पक्षपात या निष्क्रियता की किसी भी धारणा को तुरंत दूर किया जाए।

जारी: ओएसडी मीडिया, सीईओ कार्यालय, दिल्ली